



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64076-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1834/2026

मुरसलीन और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अंकित श्रीवास्तव, चौधरी दिल निसार

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री चौधरी दिल निसार ब्रीफ़ धारक श्री अनुराग कुमार चौरसिया और राज्य/प्रतिवादी 1, 2 और 3 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं।
2. अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. इस रिट याचिका में दिनांक 13.12.2025 को प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4 अभिलाष चौबे, खान निरीक्षक, खनन विभाग, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, सहारनपुर द्वारा दर्ज कराई गई और मुकदमा अपराध संख्या 635/2025 के रूप में धारा 318 (3), 338, 336 (3), 340 (2) बीएनएस, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने अधिनियम की धारा 3 (2) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा के तहत पुलिस स्टेशन-बेहट, जिला-सहारनपुर में दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी गई है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्तागण निर्दोष हैं। उन्हें उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। अंत में यह तर्क दिया गया कि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 22 में निहित प्रावधानों के अनुसार, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4 के लिए उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करना था। इसलिए, उन्होंने निवेदन किया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है, इसलिए आक्षेपित एफ.आई.आर. को इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, राज्य/प्रतिवादी 1 से 3 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान रिट याचिका का पुरजोर विरोध किया है। उनका निवेदन है कि चूंकि आक्षेपित एफ.आई.आर. के अवलोकन से संज्ञेय अपराध का स्पष्ट रूप से खुलासा होता है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा वर्तमान रिट याचिका में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान ए.जी.ए. ने न्यायालय का ध्यान आक्षेपित एफ.आई.आर. की ओर दिलाया और उसके आधार पर उनका तर्क है कि एफ.आई.आर. में उल्लिखित वाहनों के पंजीकरण नंबरों के मालिक कुछ याचिकाकर्ता संगठित अपराध में लिप्त हैं। एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों से यह भी स्पष्ट है कि एफ.आई.आर. में उल्लिखित पंजीकरण नंबरों वाले वाहनों के मालिक और चालक खान खनिज के परिवहन के दोषी हैं। चूंकि एफ.आई.आर. अभियोजन पक्ष के मामले का संपूर्ण विवरण नहीं है, देखें:-

(i) मनोज और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम (1999) 4 एससीसी 268।

(ii) सुभाष कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य, (2009) 6 एससीसी 641।

(iii) अछार सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2021) 5 एससीसी 543

अतः इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले का मूल्यांकन किया जाना है। एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के मददेनजर, न तो वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए कथनों के आधार पर और न ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आधार पर याचिकाकर्ताओं की निर्दोषता के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया विवेचना के योग्य हैं क्योंकि वे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करते

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



हैं। अतः उनका निवेदन है कि वर्तमान रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए।

6. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से पहले, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 22 को उद्धृत करना आवश्यक है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने इस पर बहुत अधिक भरोसा किया है। यह इस प्रकार है:

"22. अपराधों का संज्ञान- कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत न की गई हो।"

7. यह सर्वविदित है कि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 एक विशेष अधिनियम है। उक्त अधिनियम की धारा 22 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के संबंध में, कोई भी न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत के अलावा संज्ञान नहीं लेगा।

8. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 22, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली के तहत दंडनीय अपराध करने वाले अभियुक्त के अभियोजन की प्रक्रिया के संबंध में एक अपवाद निर्धारित करती है।

9. अधिनियम, 1952 की धारा 22 की प्रकृति और कार्यक्षेत्र तथा खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के तहत कथित अपराधों के लिए एफ.आई.आर. के माध्यम से प्रारंभ की गई आपराधिक कार्यवाही पर इसका प्रभाव, साथ ही संबंधित न्यायालय द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद न्यायालय के समक्ष परिणामी कार्यवाही, जिसमें किसी आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपपत्र दायर किया गया है, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष **राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम संजय (2014) 9 एससीसी 772** में विचार के लिए आया। सर्वोच्च न्यायालय

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ने इसमें शामिल मुद्दे से संबंधित संपूर्ण केस-लॉ के साथ-साथ सीआर.पी.सी. के प्रासंगिक प्रावधानों और खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 का मूल्यांकन करने के बाद, इसके रिपोर्ट के पैराग्राफ 69, 70, 71, 72 और 73 में निम्नलिखित अवधारित किया है:-

"69. व्याख्या के सिद्धांतों और धारा 22 में प्रयुक्त शब्दों पर विचार करते हुए, हमारी राय में, यह प्रावधान नदी तल से रेत सहित खनिजों की अवैध और बेईमानी से चोरी करने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर पूर्ण और निरपेक्ष रोक नहीं है। न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेगा कि वर्षों से भारत में नदियाँ अनियंत्रित रेत खनन की भयावह दर से प्रभावित हुई हैं, जो नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र और पुलों की सुरक्षा को नुकसान पहुँचा रही है। यह नदी तल को भी कमजोर करता है, मछली प्रजनन को प्रभावित करता है और कई जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। यदि राज्य और राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा इन अवैध गतिविधियों को नहीं रोका गया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। यह न केवल नदी के जल विज्ञान को बदल देगा बल्कि भूजल स्तर को भी कम कर देगा।"

70. एमएमडीआर अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंधों और उसमें दिए गए उपायों के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 4 और अन्य धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन गतिविधि करता है, तो अधिनियम के तहत सशक्त और अधिकृत अधिकारी को अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने सहित सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। यह भी निर्विवाद है कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर संज्ञान लेगा। अधिनियम की धारा 4 और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, पुलिस अधिकारी उक्त अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर मजिस्ट्रेट से अधिनियम के तहत संज्ञान लेने का आग्रह नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 22 में निहित निषेध, जो किसी व्यक्ति पर अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा किसी अन्य आधार पर अभियोजन चलाने से रोकता है, केवल तभी लागू होता है जब ऐसे व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाना हो, न कि किसी ऐसे कृत्य या चूक के लिए जो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध हो।

71. हालांकि, ऐसी स्थिति हो सकती है जहां कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टे या लाइसेंस या किसी प्राधिकरण के नदी में प्रवेश करता है और रेत, बजरी और अन्य खनिजों का निष्कर्षण करता है

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और उन खनिजों को राज्य के कब्जे से बेईमानी से हटाने के इरादे से गुप्त रूप से निकालता है या परिवहन करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है।

72. एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 378 के तहत परिभाषित अपराध का गहन अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि अपराध के घटक भिन्न हैं। खनन पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करना या अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए खनन गतिविधि करना एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध है, जबकि राज्य की संपत्ति, यानी नदी से राज्य की सहमति के बिना बेईमानी से रेत, बजरी और अन्य खनिजों को निकालना चोरी का अपराध है। अतः, शिकायत के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध के लिए कार्यवाही शुरू करने मात्र से पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करके रेत और खनिजों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने से नहीं रोका जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि सरकारी भूमि से रेत और बजरी की चोरी होती है, तो पुलिस मामला दर्ज कर सकती है, उसकी विवेचना कर सकती है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (घ) में दिए गए प्रावधान के अनुसार संज्ञान लेने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।

73. इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता के आलोक में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्व और राज्य की संपत्ति, नदी तल से बिना सहमति के बेईमानी से रेत और बजरी निकालना, आईपीसी के तहत एक अलग अपराध है। अतः, धारा 378 सीआरपीसी के तहत अपराध के लिए, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट एमएमआरडी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जाने वाली शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना उक्त अपराध का संज्ञान ले सकता है। फलस्वरूप, विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है और इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, इन आपराधिक अपीलों का निस्तारण संबंधित मजिस्ट्रेटों को तदनुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

10. इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कंवर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2020) 14 एससीसी 331 के मामले में, स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (उपरोक्त) के फैसले के संदर्भ में उपरोक्त उल्लिखित मुद्दे पर पुनः विचार किया और फैसले के पैराग्राफ 15 और 16 में निम्नलिखित कहा-

“15. हम संजय (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय का पुनः उल्लेख करेंगे, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के सीमा सरकार बनाम राज्य¹⁷ मामले में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को अमान्य और अवैध घोषित किया था क्योंकि मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा खान विनियमन अधिनियम की धारा 21(2) और आईपीसी की धारा 379 के तहत प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर संज्ञान लिया था, और यह टिप्पणी की थी कि संज्ञान को विभाजित नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने आगे टिप्पणी की थी कि चूंकि शिकायत खान विनियमन अधिनियम की धारा 22 के तहत नहीं की गई थी, इसलिए संज्ञान गलत और कानून के विपरीत था। हमने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय का पहले ही उल्लेख किया है जिसमें निर्देश दिया गया था कि एफआईआर को आईपीसी की धारा 379 के तहत नहीं बल्कि केवल खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 के तहत पंजीकृत माना जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के इन निर्णयों को इस न्यायालय ने संजय (उपरोक्त) मामले में सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 और उसके अर्थ का उल्लेख करते हुए निरस्त कर दिया। ‘एक ही अपराध’ अभिव्यक्ति के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 सपठित धारा 4 पर उत्पन्न अपराध और आईपीसी की धारा 379 भिन्न-भिन्न हैं। उपरोक्त तर्क के आधार पर हम अपीलकर्ता के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि एफआईआर (1995) 1 कलकत्ता एलटी 95 में उल्लिखित कार्रवाई मात्र धारा 4 का उल्लंघन है, जो कि खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है, किसी अन्य कानून के अंतर्गत नहीं। आईपीसी की धारा 379 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेने में न्यायालय पर कोई रोक नहीं है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि धारा 4 का उल्लंघन संज्ञेय अपराध होने के कारण, खान विनियमन अधिनियम के तहत कोई रोक न होने के कारण पुलिस इसकी जांच कर सकती थी, जबकि टीओएचओ अधिनियम की धारा 13(3)(iv) के तहत यह रोक है।

16. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखते हैं जिसमें माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा आईपीसी की धारा 379 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

रोकने वाले अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के अभियोग और संज्ञान को रद्द करने से इनकार किया गया है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 सपठित धारा 4, प्राधिकरण के अभाव में अभियोग और संज्ञान वैध और उचित नहीं होगा। इसके अलावा, हमारे समक्ष मौजूद कानूनी मुद्दे पर निर्णय और उत्तर देते समय हमारी टिप्पणियों को शिकायत में लगाए गए तथ्यात्मक आरोपों पर निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। अवर न्यायालय स्वतंत्र रूप से तथ्यात्मक आरोपों पर विचार करेगी और कानून के अनुसार आरोप का निर्णय करेगी। उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, क्योंकि हमने आईपीसी की धारा 379 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के अभियोग और संज्ञान को बरकरार रखा है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

11. इसके बाद, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 22 के प्रभाव से संबंधित विवाद, जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित राज्य के मामले पर लागू होता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जयंत और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) 2 एससीसी 670 में फिर से विचार के लिए आया, जिसमें न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 21, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 और 22 में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"21. इस मामले में गहन विचार-विमर्श के बाद, एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता, और इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित मामलों में दिए गए कानून के आलोक में, और उपरोक्त कारणों से, हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

21.1. माननीय मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(3) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी/एसएचओ को एमएमडीआर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली के तहत अपराधों के लिए भी अपराध मामला/एफआईआर दर्ज करने का आदेश/निर्देश दे सकते हैं और इस स्तर पर एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत निषेध लागू नहीं होगा;

21.2. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत निषेध तभी लागू होगा जब माननीय मजिस्ट्रेट एमएमडीआर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली के तहत अपराधों

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का संज्ञान लेते हैं और एमएमडीआर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली के तहत अपराधों के लिए समन/प्रविष्टि जारी करने का आदेश देते हैं;

21.3. आईपीसी के तहत अपराध के लिए, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट एमएमडीआर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की गई शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना उक्त अपराध का संज्ञान ले सकता है।

21.4. एमएमडीआर अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में, जब कोई मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(3) के तहत आदेश पारित करता है और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी/एसएचओ को अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अपराध मामला/एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है, और उसके बाद विवेचना के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन का प्रभारी/विवेचनाधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ-साथ एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित संबंधित अधिकृत अधिकारी को भेजा जा सकता है, और उसके बाद संबंधित अधिकृत अधिकारी संबंधित विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है, और उसके बाद माननीय मजिस्ट्रेट उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए संज्ञान ले सकता है, एमएमडीआर अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में समन/प्रविष्टि जारी कर सकता है, और उस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है।

21.5. यदि किसी अपराधी को धारा 23ए की उपधारा 1 के अनुसार जुर्माने का भुगतान करके अपराधों का समझौता करने की अनुमति दी जाती है, तो एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ए की उपधारा 2 को ध्यान में रखते हुए, एमएमडीआर अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

22. हालांकि, धारा 23ए की उपधारा 2 के तहत लगाया गया प्रतिबंध आईपीसी की धारा 379 और 414 के तहत अपराधों के लिए किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा और उसी पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने इमरान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2019 एससीसी ऑनलाइन एएलएल. 4542 में, उपरोक्त उल्लिखित मुद्दे पर केस-लॉ और संबंधित अधिनियम और सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद, पैराग्राफ 42, 43 और 44 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:-

"42. उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय का यह मत है कि जहां तक संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 14.04.2018 की आक्षेपित आरोपपत्र पर भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया जाना अवैध और अधिकारहीन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहां तक खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत अपराध के लिए दिनांक 14.04.2018 की आक्षेपित आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाना है, वह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 22 में निहित स्पष्ट निषेध के कारण कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है।

43. तदनुसार, दिनांक 14.04.2018 की आक्षेपित आरोपपत्र के अनुसरण में आपराधिक मुकदमा संख्या 1520/2018 की आगे की कार्यवाही, जो मुकदमा संख्या 461/2017 से उत्पन्न हुई है, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 के अंतर्गत अपराध के संबंध में केवल यही आदेश निरस्त किया जाता है और संबंधित अभियोजन पक्ष/अधिकारी को आवेदकों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

44. यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 336, 353, 307 और 379 के अंतर्गत संज्ञान लेने के आदेश के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है और संबंधित अवर न्यायालय दिनांक 14.04.2018 की आरोपपत्र के अनुसार आवेदकों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

13. अतः न्यायालयों द्वारा उपरोक्त वर्णित विधि का संयुक्त रूप से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि संबंधित न्यायालय खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 या उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान तभी ले सकता है जब इस संबंध में किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा संबंधित न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई हो।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14. उस स्थिति में क्या होगा, जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, जिसके तहत उस पर भारतीय दंड संहिता और खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया हो, और संबंधित न्यायालय ने संज्ञान लेकर मामले को राज्य का मामला मानकर कार्यवाही आगे बढ़ा दी हो, तो वह मामला अब नया नहीं रह जाता और (जयंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य) (उपरोक्त) के निर्णय के पैराग्राफ 21.4 में की गई टिप्पणियों के आधार पर समाप्त हो जाता है:-

“21.4. उल्लंघन के संबंध में एमएमडीआर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के तहत, जब कोई मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(3) के तहत आदेश पारित करता है और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी/एसएचओ को अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अपराध मामला/एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है, और उसके बाद विवेचना के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन का प्रभारी/विवेचनाधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ-साथ एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित संबंधित अधिकृत अधिकारी को भेजा जा सकता है, और उसके बाद संबंधित अधिकृत अधिकारी संबंधित विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है, और उसके बाद माननीय मजिस्ट्रेट उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए संज्ञान ले सकता है, एमएमडीआर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में समन/प्रविष्टि जारी कर सकता है, और उस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है।”

15. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता/बीएनएस आदि के अंतर्गत अपराध के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है। हालांकि, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपराध के संबंध में केवल शिकायत ही दर्ज की जा सकती है। संबंधित न्यायालय द्वारा इसमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अतः, आक्षेपित एफ.आई.आर., जहां तक यह याचिकाकर्ताओं को खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोपित करती है, विधिवत रूप से अपोषणीय है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका सफल होती है और आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

17. तदनुसार, इसे आंशिक रूप से **स्वीकार** किया जाता है।

18. दिनांक 13.12.2025 को प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4 अभिलाष चौबे, खान निरीक्षक, खनन विभाग, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, सहारनपुर द्वारा दर्ज कराई गई और मुकदमा अपराध संख्या 635/2025 के रूप में पंजीकृत एफआईआर, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 से संबंधित भाग के संबंध में रद्द की जाती है। हालांकि, एफआईआर का शेष भाग बरकरार रखा जाता है।

19. मुकदमे के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, दोनों पक्ष अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव मिश्रा, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

वाईके